इकाई 7 ग्रामीण विकास दृष्टिकोण और रणनीतियां

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 परिचय

7.2 ग्रामीण विकास

7.3 ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण

- 7.3.1 व्यापक मोर्चा दृष्टिकोण
- 7.3.2 क्षेत्रीय दृष्टिकोण
- 7.3.3 क्षेत्र दृष्टिकोण
- 7.3.4 लक्ष्य समूह दृष्टिकोण
- 7.3.5 एकीकृत/समग्र दृष्टिकोण

7.4 ग्रामीण विकास नीतियां

7.5 ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ

- 7.5.1 विश्व बैंक से सबक
- 7.5.2 ग्रामीण विकास रणनीति का वर्गीकरण

7.6 ग्रामीण विकास रणनीति के प्रकार

- 7.6.1 संसाधनों के सामूहिकीकरण पर आधारित रणनीति
- 7.6.2 विनियमित पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर रणनीति
- 7.6.3 किसान कृषि परिप्रेक्ष्य के आधार पर रणनीति
- 7.6.4 लाइसेज-फेयर या अनियमित मुक्त बाजार परिप्रेक्ष्य

7.7 सारांश

7.8 संदर्भ

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के माध्यम से जाने के बाद आप सक्षम होंगे कि :

- ग्रामीण विकास और इसके महत्व का वर्णन कर सकें;
- ग्रामीण विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों की पहचान कर सकें;
- विभिन्न ग्रामीण विकास रणनीतियों की गणना कर सकें;
- विभिन्न ग्रामीण विकास रणनीतियों के महत्व का आकलन कर सकें; और
- ग्रामीण विकास को विकास के दृष्टिकोण के रूप में बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण समय सीमा को समझ सकें।

7.1 परिचय

इस इकाई में, आपको ग्रामीण विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण और रणनीतियां अलग-अलग हो सकती हैं जो स्थिति और समय पर निर्भर करती हैं।

7.2 ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के बाहर रहने वाले लोगों की भलाई और आत्म-साक्षात्कार में सुधार करना है। सरल शब्दों में, ग्रामीण विकास को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजना माना जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य लोगों (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग) की भलाई है। (इग्नू, 2005) विश्व बैंक ने इस के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार करने की रणनीति के रूप में परिभाषित किया है।

संयुक्त राष्ट्र ग्रामीण विकास को परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें ग्रामीण समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में सुधार के लक्ष्य के साथ लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए लोगों के प्रयास स्वयं सरकारी अधिकारियों के साथ एकजुट होते हैं और उन्हें पूरी तरह से योगदान करने में सक्षम बनाते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें 1

1) ग्रामीण विकास की परिभाषा और इसके निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

7.3 ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण

बढ़ती जनसंख्या, बुनियादी ढांचे के विकास और बेरोजगारी के मुद्दे ग्रामीण विकास की प्रमुख चिंताएं हैं। विकसित और विकासशील दोनों देशों में ग्रामीण विकास एक उच्च प्राथमिकता वाली चिंता बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास देश की खाद्य आपूर्ति को बाधित कर सकता है और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का कारण बन सकता है। ग्रामीण लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को हल करने के लिए भारत में ग्रामीण विकास लाने के लिए कई दृष्टिकोण बनाए गए थे। ये दृष्टिकोण ग्रामीण पुनर्निर्माण, स्वैच्छिक प्रयास, स्व-सहायता, सहयोग और ग्राम आत्मनिर्भरता (ग्राम स्वराज)) से संबंधित गांधीवादी विचारधारा जैसी विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख वैचारिक दृष्टिकोणों के प्रमुख ढांचे की पहचान करना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है–

a) पितृसुलभ

b) जनवादी

c) तकनीकी तंत्र

d) आमूल परिवर्तन/आंदोलन

बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में कई ग्रामीण विकास प्रयासों में पैतृक दृष्टिकोण अपनाया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों (सीडीपी) ने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाई है। इस दृष्टिकोण का तरीका गांव में एक सरकारी अधिकारी को शामिल करना है जो ग्रामीणों के ''मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र'' के रूप में कार्य करेगा, जो उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास के बारे में आधुनिक और वैज्ञानिक विचारों से परिचित कराने के लिए आवश्यक है। सीडीपी का उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए इस दृष्टिकोण की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना है।

पंचायती राज और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर जोर देने के कारण हाल के दिनों में लोकलुभावन जनवादी दृष्टिकोण अधिक प्रमुख हो गया है। इस दृष्टिकोण में, सरकार की भूमिका स्थानीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना है। इस दृष्टिकोण में, यह माना जाता है कि ग्रामीण लोग परिवर्तन में महत्वपूर्ण रुचि रखते हैं और यदि उन्हें ऐसा करने का अवसर मिलता है तो वे अपने जीवन को बदल सकते हैं क्योंकि ग्रामीण समुदाय ही अपनी जरूरतों के प्रति संपूर्ण न्याय कर सकता है। इस दृष्टिकोण में विकास गतिविधियों का प्रस्तावित पैटर्न नीचे से डिजाइन किया गया है।

तकनीकी तंत्र दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है। यह अक्सर संस्थागत, वितरण या पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के लिए चिंता की अनदेखी करता है। 1960 और 1970 के दशक की अवधि वह चरण था जब भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था। हालांकि, यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से कृषि उत्पादकता में सुधार पर केंद्रित था, लेकिन खाद्य सुरक्षा में सुधार और गरीबी को कम करने में विफल हो सकता है।

आमूल परिवर्तन/आंदोलन दृष्टिकोण भूमि सुधार के माध्यम से धन और आय के पुनर्वितरण पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण के पीछे मुख्य उद्देश्य मौजूदा ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को सीधे चुनौती देना है। इसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन के साथ शक्ति और प्रभाव का पुनर्वितरण इस तरह करना है कि इसके जरिये समाज के वंचित वर्ग को लाभान्वित किया जा सके। (ग्रिफिन 1973) सामान्य समझ यह है कि असमान शक्ति संबंध, परिसंपत्तियों के लिए अंतर पहुंच के आधार पर, अंतर गरीबी का मूल कारण हैं। कभी-कभी इस दृष्टिकोण के समर्थक समाजवादी आदर्शों (ली और चौधरी 1983) (ली और चौधरी 1983) से प्रेरित होते हैं। यह दृष्टिकोण चीन के पहले दो दशकों के अनुभव पर आधारित था।

7.3.1 व्यापक मोर्चा दृष्टिकोण

इस दृष्टिकोण में सभी प्रमुख मोर्चों पर ग्रामीण समस्याओं पर एक साथ 'हमला" करने की परिकल्पना की गई थी ताकि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) शुरू किया गया था। सीडीपी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र

विकास करना है-जैसे कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों का विकास, कुटीर और लघु उद्योगों का विकास, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रावधान, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति और सड़कों, बिजली, सिंचाई, संचार आदि के माध्यम से आर्थिक बुनियादी ढांचे का सृजन। सीडीपी को लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ पूरे ग्रामीण समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तैयार डिजाइन किया गया है।

7.3.2 क्षेत्रीय दृष्टिकोण

यह दृष्टिकोण लीबेनस्टीन की महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास थीसिस पर आधारित था, जो अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयासों का आह्वान करता है। इसका लक्ष्य है, आर्थिक विकास के एक प्रमुख इंजन कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास करके कृषि अर्थव्यवस्था को तेजी से और सतत विकास के मार्ग पर लाना है। कृषि क्षेत्र के अलावा, पशुपालन जैसे कृषि से संबद्ध ग्रामीण लोगों की आय को बढ़ाने और स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इनमें गहन कृषि जिला कार्यक्रम (आईएडीपी), गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (आईएएपी)) और गहन मवेशी विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) शामिल हैं।

7.3.3 क्षेत्र दृष्टिकोण

चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान नीति निर्माताओं ने महसूस किया कि ग्रामीण विकास के लिए पहले के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई है। यह महसूस किया गया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में सामाजिक-आर्थिक और भौतिक विभिन्नताओं वाले क्षेत्रों के लिए कोई भी दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं था। यह सोचा गया था कि क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देकर वृद्धि और विकास में अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर सकता है। इसलिए, सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, सूखा प्रवण क्षेत्रों आदि जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने की परिकल्पना की गई थी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं - पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) (जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टीएडीपी) (टीएडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) (लक्ष्य समूह दृष्टिकोणयह महसूस किया गया कि यद्यपि क्षेत्र दृष्टिकोण कार्यक्रमों ने विशिष्ट क्षेत्रों के विकास को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन समाज का एक निश्चित वर्ग अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर समूह, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर वांछित रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं। इसलिए गरीबी उन्मूलन और कमजोर वर्गों के बीच रोजगार पैदा करने के लिए कतिपय लक्ष्य-विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास अभिकरण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अन्य संबंधित कार्यक्रम शुरू किए गए।

7.3.4 एकीकृत दृष्टिकोण

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी और बढ़ती बेरोजगारी की दोहरी समस्याओं के समाधान के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का विचार किया गया। यह पता चला कि अकेले अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि विकास के फल को उन गरीबों के लिए ''ट्रिकल-डाउन'' करने की सुविधा नहीं दे सकती है जो सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान पर हैं। ट्रिकल डाउन सिद्धांत के अनुसार- समाज के सबसे गरीब लोग समाज के सबसे अमीर लोगों की बढ़ती संपत्ति के परिणामस्वरूप लाभान्वित होते हैं। इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) 1978 में शुरू किया गया था। आईआरडीपी एक बहु-स्तरीय, बहु-क्षेत्र, बहु-खंड कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण समुदायों के विभिन्न वर्गों से संबंधित पारस्परिक रूप से सहायक परियोजनाएं और गतिविधियां शामिल हैं। इस दृष्टिकोण का मुख्य फोकस ग्रामीण गरीबों को आय-सृजन परिसंपत्तियां और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 2

1) सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के मुख्य फोकस की व्याख्या कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2) ट्रिकल-डाउन प्रभाव और इसके परिणामों को समझाएं।

.....

.....

.....

.....

.....

7.4 ग्रामीण विकास नीतियां

ग्रामीण विकास नीति और प्रथाओं के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में और क्षेत्रीय विकास में अनुसंधान के क्षेत्र में उभरा है। विश्व बैंक द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए स्पष्ट रूप से आह्वान करने के बाद इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास पर विश्व बैंक नीति का मसौदा, 2000) बैंकिंग गतिविधियों पर केंद्रित है जो ग्रामीण विकास और ग्रामीण जीवन में सुधार और प्रतिस्पर्धात्मकता कृषि और ग्रामीण व्यवसाय बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए नीतिगत सुधारों का समर्थन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और सामाजिक और संस्थागत विकास के मुद्दों को सतत विकास आवश्यकताओं के

संदर्भ में भी संबोधित किया जाता है। ग्रामीण विकास नीति को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विकास के पिछले दृष्टिकोणों के साथ उभरे असंतोष के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था। यह महसूस किया गया कि विकास की स्थापित परिभाषा न्यायसंगत नहीं है और यह ज्यादातर शहरी स्थानों पर केंद्रित है। विकास का उद्देश्य न्यायसंगत होना चाहिए और इसलिए विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसी विकास एजेंसियों द्वारा विकास दृष्टिकोणों का पुनः संशोधन शुरू किया गया था।

ग्रामीण विकास नीतियां शब्द एक राष्ट्रीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में राज्य द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के निश्चित दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो केवल कृषि विकास की तुलना में व्यापक और विशिष्ट है। ग्रामीण विकास की नीतियां कृषि और कृषि से संबंधित नीतियों के विकास से अधिक हैं। ग्रामीण विकास नीतियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ कृषि के अन्य महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि और विकास पैदा करने पर अधिक केंद्रित हैं। ग्रामीण विकास नियोजन प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक कारकों पर विचार करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्षेत्र के संवर्धन के लिए एक अंतर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आर्थिक प्रगति के लिए आंतरिक हैं। ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना सरकार पर निर्भर करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों के विभिन्न सेट अपनाए गए थे। भूमि, प्रौद्योगिकी, कृषि, रोजगार, शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण नीतियां हैं जो अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यनीतियों में आम हैं। ग्रामीण विकास पर हैरिस (1982) के दृष्टिकोण के अनुसार ग्रामीण विकास नीतियों को परिभाषित किया जा सकता है;

- एक राज्य के नेतृत्व वाली गतिविधि और ग्रामीण विकास के लिए एक केंद्रित विकास नीति।
- ग्रामीण समाजों में परिवर्तन के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के हस्तक्षेप द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

ये दोनों बिंदु ग्रामीण विकास पर नीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन दो धारणाओं के अनुसार, यह संभवतः राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कारक के रूप में जोड़ता है। विकसित देशों में, यह आवश्यक रूप से राज्य सरकार को शामिल नहीं करता है, बल्कि ग्रामीण विकास नीतियों के निर्माण में बाजार तंत्र को भी आकर्षित करता है। लेकिन विकासशील देशों में, ग्रामीण विकास के विषयों पर नीति निर्धारण प्रक्रिया सरकार की जिम्मेदारी है।

किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण सहित भूमि सुधार ग्रामीण समाजों को बदलने के प्राथमिक साधनों में से एक है। भूमि सुधार और एक भूमि नीति (जो वितरणात्मक न्याय प्रदान करना चाहती है) के परिणामस्वरूप अधिक कृषि उत्पादकता भी हो सकती है। इसलिए, भूमि नीति ग्रामीण विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

मौसम के प्रभाव से कृषि को बचाने में तकनीकी सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण समाजों की मूल समस्याएं बेरोजगारी और कम उत्पादकता हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, तथ्य यह है कि हमें ग्रामीण विकास के लिए नई तकनीक अपनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियां बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए जो न केवल कृषि उपज की उत्पादकता और गुणवत्ता को बल्कि पर्यावरण में संतुलन भी बनाए रखें। ग्रामीण विकास कार्यनीतियों को अपने कार्यक्रम तैयार करते समय इसे ध्यान में रखना होगा।

कृषि नियोजन ग्रामीण विकास रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसे देश में। प्रभावी कृषि योजना के तहत ग्रामीण विकास रणनीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और छोटे किसानों सहित किसानों की कृषि आय बढ़ाना होना चाहिए। कृषि क्षेत्र का संतुलित विकास इस क्षेत्र पर निर्भर लोगों के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अनुसंधान और विस्तार ग्रामीण विकास रणनीतियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अनुसंधान ग्रामीण संस्कृतियों के लिए उपयुक्त ज्ञान में आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। अनुसंधान उन विचारों का स्रोत बनते हैं जो संस्थानों को ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान तलाशने में मदद करने के साथ प्रकृति संरक्षण में लोगों की भागीदारी का एक तंत्र विकसित करेंगे।

ग्रामीण विकास के लिए कार्यनीतियां बनाते समय ग्रामीण समाजों के संस्थागत पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि रणनीति की प्रभावशीलता और इसके परिणाम ग्रामीण समाज के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचने योग्य होने चाहिए।

अपनी प्रगति की जाँच करें 3

1) कृषि योजना क्या है? ग्रामीण विकास में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

7.5 ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ

ग्रामीण विकास के उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रगति और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के इर्द-गिर्द घूमते हैं। ग्रामीण विकास का पारंपरिक दृष्टिकोण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने और ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है।

विश्व बैंक के अनुसार, ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण विकास को उनकी ''जुड़ाव'' के कारण क्रॉस-सेक्टोरल संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास का लक्ष्य भी समय के साथ बदलता गया है। 1990 के दशक में, विकास का उद्देश्य एजेंडा बाजार आधारित खाद्य और कृषि उत्पादों पर अधिक केंद्रित था। बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की पेशकश करने के लिए हॉप के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका शुरू की गई थी। विकास के बाद के चरण में, ग्रामीण विकास की रणनीति अधिक सामुदायिक और आजीविका आधारित हो गई। गरीबी आकलन और उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1993 में, ग्रामीण विकास पर विशेषज्ञ समूहों ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने पर ध्यान दिया, क्योंकि क्योंकि गरीबी रेखा राज्य की वृद्धि और विकास के आंकड़ों के अनुसार राज्य द्वारा भिन्न होती है। विशेषज्ञ समूहों की इस रणनीति ने लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के गरीब वर्ग के लिए केंद्रित विकास

के प्रयास करने के लिए काम किया। जिन्होंने विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्षेत्र में शामिल ग्रामीणों के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और बॉटम अप (नीचे से उपर की ओर) दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह के दृष्टिकोण और विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास और इसकी रणनीतियों के दायरे को और विस्तार दिया।

7.5.1 विश्व बैंक से सबक

विश्व बैंक ने ग्रामीण विकास के लिए अपनी रणनीति में कुछ महत्वपूर्ण घटकों को अपनाया जिसमें कृषि और गैर-कृषि दोनों गतिविधियां शामिल हैं। ये घटक निम्नलिखित हैं :

1) **कृषि विकास की बहाली**

आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण और खुले बाजार की नीति के कारण, 1990 के दशक में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भारी वृद्धि देखी गई। नतीजतन, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा होने से कृषि उत्पादों के मामले में भारी नुकसान हुआ। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने नीतिगत बदलावों पर जोर दिया जिसमें कृषि में परिवर्तन, निजी भूमि स्वामित्व, कृषि आधारित उत्पाद प्रसंस्करण के निजीकरण को बढ़ावा देना, कृषि विपणन और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी शामिल हैं। इसका उद्देश्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना और बेरोजगार ग्रामीण युवा आबादी के लिए गैर-कृषि भूमि रोजगार पैदा करना था।

2) **गैर-कृषि ग्रामीण विकास का विस्तार**

बाद में विश्व बैंक ने ग्रामीण विकास रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया, जो इसे सीधे ग्रामीण आबादी के जीवन से जोड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, सूक्ष्म ऋण सहित ग्रामीण वित्तीय सेवाओं, गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों और ग्रामीण प्रशासन पर अधिक जोर दिया गया।

3) **गरीबी उन्मूलन पर अधिक जोर**

आजकल, विश्व बैंक की रणनीति गरीबी उन्मूलन प्रयासों पर अधिक केंद्रित है इस रणनीति के लिए, विश्व बैंक को कुछ उपायों की आवश्यकता थी, जिनमें शामिल हैं;

क) अपेक्षाकृत गरीब देशों और गरीब क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

ख) निम्न आय वर्ग की आबादी और उनके द्वारा उत्पादित फसलों के उपायों से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान देना।

ग) स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक संसाधनों जैसे गरीबों की सेवा करने वाली सामाजिक परिसंपत्तियों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अधिक समय और संसाधन निवेश।

घ) मोल्दोवा, अल्बानिया, किर्गिज गणराज्य और लातविया के क्रेडिट आधारित मॉडल अजरबैजान, जॉर्जिया और मोल्दोवा भूमि आधारित मॉडल और अल्बानिया के बाजार आधारित मॉडल तक गरीबों की पहुंच को सुनिश्चित करना।

ङ) गरीबी उन्मूलन और सिंचाई पुनर्वास सुविधाओं पर अधिक जोर।

4. **सामुदायिक विकास पर अधिक जोर**

विश्व बैंक ने पाया कि कृषि सहायता सेवाएं, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, सिंचाई, सूक्ष्म ऋण और प्राकृतिक संसाधन कार्यक्रम स्थानीय भागीदारी की मदद से अच्छी तरह से योजनाबद्ध हैं। इन अनुभवों ने ग्रामीण समुदाय को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिक आर्थिक रूप से तर्कसंगत सुधार करने का मार्ग प्रशस्त किया। यह भी देखा गया कि विकास रणनीतियों को सफल बनाने में पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी महत्वपूर्ण है।

7.5.2 ग्रामीण विकास रणनीति का वर्गीकरण

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अलग-अलग विचारधाराएं विकास के अलग-अलग तरीके सुझाती हैं लेकिन यह महसूस किया गया कि ग्रामीण विकास के लिए कोई एक सार्वभौमिक तरीका नहीं है। यहां हम कुछ रणनीतियों के बारे में जानेंगेः

प्रौद्योगिकी अंतर रणनीति

1950 के दशक के दौरान एक प्रमुख राय उभरी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अल्पविकास का मुख्य कारण कृषि और संबद्ध गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग था। इसलिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा विकसित और अविकसित क्षेत्रों के बीच प्रौद्योगिकी अंतर को भरने का प्रयास किया गया था।

1) **संसाधन-अंतर रणनीति**

चूंकि प्रौद्योगिकी अंतर रणनीति वांछित परिणाम नहीं लाती थी, इसलिए 60 के दशक के दौरान संसाधन-अंतर रणनीति पर जोर दिया जाने लगा। यह महसूस किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र अपर्याप्त संसाधनों से पीड़ित हैं, इसलिए सहायता और पूंजी ऋण प्रदान करके इस संसाधन अंतर को भरने की आवश्यकता थी।

2) **संगठनात्मक-अंतर रणनीति**

इस रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि प्रौद्योगिकी और संसाधनों की बहुत आवश्यकता है लेकिन वे एक सशक्त संगठनात्मक व्यवस्था सेटअप के बिना विकास नहीं ला सकते हैं। 1970 के दशक में यह महसूस किया गया कि ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और अल्प-रोजगार और सामाजिक न्याय या विकास लाभों के समान वितरण जैसी समस्याओं पर कोई वांछित प्रभाव नहीं पड़ा।

3) **अन्योन्याश्रितता रणनीति**

यह रणनीति कृषि और उद्योग क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण है। विकास की प्रक्रिया में कृषि और उद्योग के बीच सही संबंध प्रदान करने वाली विवेकपूर्ण विकास रणनीति अपनाकर कृषि में सुधार करना महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कृषि उपज से उत्पादकता और लाभ बढ़ाने के लिए अन्योन्याश्रितता की यह रणनीति आवश्यक है। संबद्ध क्षेत्र जैसे परिवहन, गोदाम, खाद्य प्रसंस्करण कुछ कृषि-निर्भर उद्योग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें 4

1) ग्रामीण विकास में सामुदायिक सहभागिता की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

7.6 ग्रामीण विकास रणनीतियों के प्रकार

ग्रामीण विकास पहलों में ग्रामीण लोगों के जीवन के कृषि और गैर-कृषि दोनों पहलू शामिल हैं। ग्रामीण विकास रणनीतियां निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं:

- न्यूनतम लागत पर कृषि उत्पादन में वृद्धि।
- ग्रामीण आबादी के कल्याण में समग्र सुधार।
- मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था का परिवर्तन और आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करना।
- संसाधन जुटाना।
- एकीकृत तरीके से सेवाओं का प्रावधान।
- प्रशासन की जवाबदेही।
- ग्रामीण विकास लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और संचालन ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा करने में परिलक्षित होते हैं।

ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियां कृषि संबंधों और उत्पादन की तकनीकों के विभिन्न पहलुओं पर जोर देती हैं और महत्व देती हैं। ग्रामीण विकास के लिए अपनाई गई विभिन्न ग्रामीण रणनीतियां इस प्रकार हैं:

7.6.1 संसाधनों के सामूहिकीकरण पर आधारित रणनीति

ग्रामीण परिसंपत्तियों के सामूहिकीकरण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। भूमि के निजी स्वामित्व को समाप्त किया जाता है ताकि भूमि के स्वामित्व और भूमि उपयोग में असमानता अधिक उत्पादक हो सके। भूमि की उत्पादकता इसलिए प्राप्त की जाती है क्योंकि भूमि के एक छोटे से टुकड़े को समेकित किया जा सकता है ताकि बड़े पैमाने पर खेती कृषि उत्पादन में बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं को ला सके। ट्रैक्टर, सिंचाई और हार्वेस्टर के रूप में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बड़े पैमाने पर खेती संभव है। इस रणनीति को अपनाकर सोवियत संघ, चीन और पूर्वी यूरोपीय देशों ने अपने कृषि उत्पादों को बढ़ाया।

7.6.2 विनियमित पूंजीवादी दृष्टिकोण के आधार पर रणनीति

विनियमित पूंजीवादी दृष्टिकोण पर आधारित दूसरी रणनीति एक पूंजीवाद और किसान क्षेत्र के सह-अस्तित्व की कल्पना करती है जिसे राज्य से कुछ समर्थन और संरक्षण

मिलता है। इस रणनीति में यह माना गया था कि बड़े पैमाने पर विकास का उद्देश्य पूंजीवादी क्षेत्र द्वारा ध्यान रखा जाएगा, जबकि किसान क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या का समाधान तब तक करेगा जब तक कि गैर-कृषि क्षेत्र तेजी से बढ़ना शुरू नहीं हो जाते। इस रणनीति की आलोचना की गई है क्योंकि इस रणनीति में ग्रामीण असमानताओं को नजरअंदाज किया जाता है। पूंजीवादी हित और किसान क्षेत्र दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन होना चाहिए।

7.6.3 किसान कृषि दृष्टिकोण के आधार पर रणनीति

किसान कृषि परिप्रेक्ष्य रणनीति भूमि के पुनर्वितरण और भूमि संबंधों के ओवरहाल के लिए तर्क देती है। इसमें छोटी किसान इकाइयों के लिए मजबूत समर्थन की परिकल्पना की गई है, जिन्हें विकास और रोजगार के दोहरे उद्देश्यों का ध्यान रखना है। किसानों को सभी के लिए कृषि छोड़ने से बचाने के लिए यह रणनीति अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। लंबे समय तक कृषि करने में अपनी प्रेरणा जारी रखने के लिए एक किसान के लिए कृषि भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण है।

दूसरी और तीसरी दोनों रणनीतियों में, यह परिकल्पना की गई है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ताकि कृषि पर अधिशेष श्रम के दबाव को कम किया जा सके और सभ्य आजीविका विकल्पों के निर्माण को सुविधाजनक बनाया जा सके। जीवंत कृषि क्षेत्र में गैर-कृषि अवसरों के सृजन के लिए मजबूत आवेग होंगे, लेकिन इस तरह के आवेग का दोहन करने के लिए राज्य से महत्वपूर्ण कार्य करने की उम्मीद की जाती है।

7.6.4 अबंध/अहस्तक्षेप नीति या अनियमित मुक्त बाजार के दृष्टिकोण

चौथा, मुक्त बाजार या पूंजीवादी रणनीति, यह माना जाता था कि अमीर जमींदार अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि में भूमिका निभाएंगे। इस रणनीति में यह सुझाव दिया गया है कि राज्य को पूंजीवादी क्षेत्र के विस्तार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और स्वामित्व पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। इस रणनीति में, असमानता और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को गैर-मुद्दे माना जाता है। इस रणनीति में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रत्येक भागीदार को अधिकतम समर्थन को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के संबंध में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में, मुक्त बाजारोन्मुख पूंजीवादी रणनीति बढ़ रही है। न केवल भारत में बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी यह देखा जा सकता है जहां अधिकतम कृषि आधारित उत्पाद निगमीकरण बढ़ रहा है। हालांकि, किसान क्षेत्र के अधिकारों और विकल्पों की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

ग्रामीण विकास रणनीति की मुख्य चिंताओं को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

क) संस्थान निर्माण गतिविधियों के एक भाग के रूप में किसानों के लिए कृषि अनुसंधान, विस्तार, ग्रामीण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ख) सिंचाई, परिवहन, संचार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण की गतिविधि।

ग) कृषि आदानों के वितरण के लिए विपणन सुविधाओं में सुधार।

घ) भूमि अवधि, कृषि उत्पादन मूल्यों और कृषि आय के कराधान से संबंधित नीतियां।

बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव के आधार पर भूमि के वितरण के प्रति दृष्टिकोण और कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों के प्रकारों को एकल मॉडल यानी यूनि-मॉडल और द्विमॉडल यानी बाई-मॉडल के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। एक यूनि-मॉडल रणनीति वह है जिसमें भूमिधारण को समान रूप से वितरित किया जाता है। जापान, ताइवान और कोरिया के मामले में इस रणनीति को जबरदस्त सफलता मिली।

यूनि-मॉडल कृषि विकास अधिकांश ग्रामीण परिवारों को पूंजी बचत प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित उच्च कृषि उत्पादकता के कारण श्रम कार्यों में वृद्धि के माध्यम से कृषि से बढ़े हुए उत्पादन का आनंद लेने की अनुमति देता है। हरित क्रांति इस का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण लाभ है क्योंकि यह अधिकतम श्रम और भूमि का उपयोग कर सकता है जो विकासशील देशों के मुख्य संसाधन हैं। एक द्विमॉडल विकास रणनीति में, विकसित देशों से आयातित पूंजी गहन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बड़े किसानों के अल्पसंख्यक की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि के साथ कृषि विकास होता है। जॉनसन और किल्बी (1975) क्रमशः एकल मॉडल और द्विमॉडल कृषि विकास के दो अलग-अलग उदाहरणों के रूप में ताइवान और कोलंबिया का उपयोग करते हैं।

ताइवान में हर पांच में से चार खेतों का औसत आकार एक एकड़ है और औसत शीर्ष पर इससे 11.6 गुना आकार अर्थात् तीन एकड़ यानी करीब 1.2 हेक्टेअर आकार वाले खेतों की संख्या करीब एक प्रतिशत है। दूसरी ओर, कोलंबिया में मात्र 1.10 खेत पांच एकड़ आकार के हैं, जबकि शीर्ष आकार पर 56 एकड़ आकार के खेत आते हैं, जो सामान्य खेत के आकार से करीब 46 गुना हैं। जॉनसन और किल्बी (17, 1975)

महत्वपूर्ण कारक भूमि वितरण से संबंधित है। यदि भूमि बेहद असमान रूप से वितरित की जाती है, तो अधिकांश कृषि भूमि छोटी होगी और कुछ बड़ी होगी। भूमि वितरण भूखंड में इस संरचना की अभिव्यक्ति इस अर्थ में द्विमॉडल होगी कि भूमि को बड़े भूमि भूखंडों पर एक मोड के साथ वितरित किया जाएगा, जबकि कृषि भूमि का वितरण भूमि के निचले स्तरों पर एक अलग मोड प्रदर्शित करेगा। एक द्विमॉडल भूमि संरचना राजनीतिक अर्थव्यवस्था के माहौल के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाती है जिसमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग अपने पक्ष में सार्वजनिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं। संस्थागत ढांचे में द्वि-मॉडल कृषि विकास रणनीति केवल भूमि वितरण तंत्र से कहीं अधिक है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 5

1) भारत के कृषि विकास में भूमि सुधारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

7.7 सारांश

विकास के अनुभव से पता चलता है कि केवल आर्थिक विकास से जीवन स्तर बेहतर नहीं होगा। यह महसूस किया गया है कि हमें लाभार्थियों की विविधता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह महसूस किया गया कि विकासशील देशों में गरीबी की समस्या को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, विशेष रूप से हमारे जैसे जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करती है। ग्रामीण विकास में, आर्थिक विकास के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ढांचागत सुविधाएं, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन जैसे अन्य कारक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। वितरणात्मक न्याय की चिंता ऐसी रणनीतियां बनाते समय भी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है जहां विकास का परिणाम छोटे और बड़े किसानों सहित ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक योगदान करने वाले सदस्य तक पहुंचेगा।

यह महसूस किया जाता है कि बेहतर समझ के लिए, हमें ग्रामीण विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों और रणनीतियों को विकसित करना होगा क्योंकि एक ही दृष्टिकोण और रणनीति काम नहीं कर सकती है। प्रत्येक विकासशील देश विविध वातावरण के अनुकूल एक रणनीति तैयार करना मुश्किल है।

7.8 संदर्भ

असलम, एम। 1993: एशिया में एकीकृत ग्रामीण विकास, मनोहर, नई दिल्ली।

ग्रिफिन, के। ग्रामीण विकास के लिए नीतिगत विकल्प। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के ऑक्सफोर्ड बुलेटिन, 35(4), पृ. 239-274।

जी. श्रीधर और डी. राजशेखर, 2014: भारत में ग्रामीण विकासः रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ, अवधारणा. नई दिल्ली।

हैरिस, जे (1982)। ग्रामीण विकासय किसान अर्थव्यवस्था और कृषि परिवर्तन के सिद्धांत।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2005: ''ग्रामीण विकास-भारतीय संदर्भ'' ब्लॉक 2 पर पाठ्यक्रम सामग्री, स्कूल ऑफ कंटीन्यूइंग एजुकेशन, इग्नू, नई दिल्ली।

जॉनसन, बीएफ और किल्बी, पी। कृषि और संरचनात्मक परिवर्तनय देर से विकासशील देशों में आर्थिक रणनीतियों। कृषि और संरचनात्मक परिवर्तन देर से विकासशील देशों में आर्थिक रणनीतियों।

ली, डी.ए.एम. और चौधरी, डी.पी., 1983. ग्रामीण विकास और राज्यय विकासशील देशों में विरोधाभास और दुविधाएं।

सिंह, करतार 2009।ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियां और प्रबंधन, ऋषि प्रकाशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, नई दिल्ली।